शादीशुदा मर्द को जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए मजबूर करना महिला को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगा दी नो-कॉन्टैक्ट की मुहर

नई दिल्ली। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एक अनोखे मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए एक शादीशुदा महिला को एक पुरुष और उसके परिवार का पीछा करने, परेशान करने और उससे किसी भी तरह का संपर्क करने से रोक लगा दिया है। यह मामला तब सामने आया जब एक शादीशुदा पुरुष ने कोर्ट में याचिका दायर कर महिला के उत्पीड़न और धमकियों से सुरक्षा की गुहार लगाई। व्यक्ति ने कोर्ट को बताया कि महिला उससे शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए दबाव डाल रही थी और उसका लगातार पीछा कर रही थी। यह फैसला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामले महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित होते हैं। याचिकाकर्ता पुरुष जो एक परिवार वाला व्यक्ति है ने कोर्ट को बताया कि महिला उससे शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए दबाव डाल रही थी और उसका लगातार पीछा कर रही थी।

बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 193 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 01 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

झुग्गी-झोपड़ी वालों के हक की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस, हजारों गरीब परिवार त्रासदी से जूझ रहे- देवेंद्र यादव

नई दिल्ली।

दिल्ली में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़े जाने पर चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार की आलोचना करी है. देवेंद्र यादव ने कहा कि दो बार अस्वीकार करने के बाद संसद में कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया परंतु झुग्गी झोपड़ियों के विषय पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए वक्तव्य पर सरकार द्वारा चर्चा न करना बीजेपी के गरीब विरोध मुखौटे को उजागर करता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की 3000 झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 15 हजार से अधिक गरीब लोगों के विस्थापन पर जवाबदेही से भागना बीजेपी की गरीब विरोधी नीति और संसद में लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने का षड्यंत्र उजागर करता है. देवेंद्र यादव ने कहा कि 15 हजार से अधिक गरीब परिवार जो त्रासदी से जूझ रहे है, उनका जल्द समाधान किया जाए, जबकि दिल्ली की बीजेपी सरकार दिल्ली में तोड़फोड़ अभियान चलाकर उनका उजाड़ा गया जिसमें वैधानिक और न्यायिक सुरक्षा उपायो का उलंघन करके हजारों झुग्गीवासियों को आश्रय से वंचित होना पड़ा. यादव ने कहा कि बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़कर दिल्ली झुग्गी एवं झुग्गी पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति, 2015 का उल्लंघन कर रही है. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 01.01.2006 से पहले मौजूद झुग्गी बस्तियों को वैकल्पिक आवास के बिना हटाया नही जा सकता, 01.01.2015 तक अधिसूचित झुग्गी बस्तियों में झुग्गियों को वैकल्पिक आवास के बिना तोड़ा नहीं जा सकता और 01.01.2015 के बाद नए अतिक्रमणों को पर्याप्त

नोटिस, तीन महीने के अस्थायी आवास और बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के बाद ही हटाया जाना चाहिए. परंतु बीजेपी सरकार ने किसी भी व्यवस्था का सम्मान न करके बेरहमी से दिल्ली के 15 हजार लोगों को उजाड़कर बेघर कर दिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोकसभा में सातों सांसद को झुग्गी झोपड़ी विस्थापन के विषय संसद में आवाज उठानी चाहिए परंतु उन्हें झुग्गीवालों के दुखों से कोई सरोकार नही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनावों के दौरान झुग्गीवालों के बीच उनकी बस्तियों में रात्रि प्रवास करके 3.5 लाख पक्के घर देने, यथास्थान पुनर्वास, बुनियादी नागरिक सेवाएं, स्वामित्व अधिकार और सामाजिक कल्याणकारी उपायों के जहां झुग्गी वही मकान देने के वादे को तोड़कर अपने पांच महीने के शासन में बीजेपी सरकार ने 3000 झुग्गियों को उजाड़कर 15000 से अधिक लोगों को बेघर कर दिया. देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने दिल्ली में 40-50 वर्षों रह रहे गरीब लोगों को उजाड़कर न्यायिक आदेश का उलंघन किया, जिसमें अजय माकन बनाम भारत संघ 2019 में उच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें 2015 की डीयूएसआईबी नीति का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया था कि उचित पुनर्वास प्रक्रिय के बिना बेदखली पर रोक लगाता है, फिर भी जेलरवाला बाग जेजे कलस्टर में दो घरों को मौजूदा अदालती रोक के बावजूद बुलडोजर से गिरा दिया गया. उन्होंने कहा कि यही नहीं तोड़फोड़ की कार्यवाही करके दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम 2010 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान द्वितिय अधिनियम 2011 के तहत वैधानिक सुरक्षा उपायों का भी उलंघन किया. देवेंद्र यादव ने कहा कि तानाशाह बीजेपी गरीब विरोधी रवैया अपना रही है, जिसके तहत दिल्ली से झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है. ऐसा करके बीजेपी ने अपना गरीब विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस चुप नही बैठेगी. देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी के आदेश पर कांग्रेस पार्टी झुग्गी झोपड़ी वालों के हितों की रक्षा, सुरक्षा, उनको विस्थापित करने और सरकार जब तक गरीब लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था नही कर देती तब तक उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे. 675 जेजे कलस्टर के लिए कानूनी सहायता सहित कांग्रेस पार्टी झुग्गी वालों की आवाज बनकर 15 दिन का अभियान शुरू करेंगे.

एसबीके सिंह को मिला दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसबीके सिंह को दिल्ली के पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एजीएमयूटी कैडर के 1988 बैच के अधिकारी एसबीके सिंह वर्तमान में दिल्ली में होमगार्ड्स के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति मिलने पर, वह 1 अगस्त, 2025 से अगले आदेश तक दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। यह घोषणा गृह मंत्रालय के निदेशक (सुरक्षा) अनीश मुरलीधरन द्वारा हस्ताक्षरित एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से की गई। यह निर्णय दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों में प्रशासनिक फेरबदल के तहत लिया गया है। 36 वर्षों से अधिक के शानदार करियर के साथ, सिंह ने दिल्ली पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और दो पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में पुलिस बल के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज के पूर्व छात्र, सिंह 1986 में स्नातक होने के बाद भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। बाद में उन्होंने मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ एमबीए किया। उनका पुलिसिंग करियर क्षेत्रीय अनुभव, प्रशासनिक नवाचार और तकनीकी दूरदर्शिता का एक अद्भुत मिश्रण दर्शाता है। दिल्ली पुलिस में, सिंह ने दक्षिण के अतिरिक्त डीसीपी और उत्तर-पूर्व तथा मध्य दोनों जिलों में डीसीपी जैसे प्रमुख पदों पर कार्य किया है।

बाद में उन्होंने आर्थिक अपराध शाखा का नेतृत्व किया और खुफिया, सुरक्षा, कानून और व्यवस्था तथा प्रौद्योगिकी और परियोजना कार्यान्वयन सहित विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त पुलिस आयुक्त और विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य किया।

विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में, आईपीएस अधिकारी ने पुलिस थानों में जन सुविधा डेस्क की शुरुआत की और 89 पुलिस थानों वाले सात पुलिस जिलों में प्रमुख व्यवस्थाओं और जाँचों का पर्यवेक्षण किया। विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में, सिंह ने उच्च-स्तरीय सुरक्षा अभियानों का नेतृत्व किया, विशेष रूप से 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा के दौरान गणतंत्र दिवस समारोह और उसी वर्ष भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन, जिसमें 54 राष्ट्राध्यक्षों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया था।

बिना चालक वाली मेट्रो में महिलाएं निहार रहीं विहंगम नजारा, इन ट्रेनों से ऑपरेटर का केबिन हटाया गया

नई दिल्ली। इन दिनों बिना चालक वाली मेट्रो ट्रेन में महिलाएं दिल्ली का विहंगम नजारा देख पा रही हैं। मेट्रो ने ट्रेन के अगले कोच के ऑपरेटर केबिन को हटा दिया है तो अब महिलाएं ट्रेन के आगे निहारते हुए सफर का आनंद ले रही हैं। ये अनुभव महिलाओं के लिए बिलकुल नया है।

अभी तक कोच में दो तरफ लगे शीशों से ही अगल-बगल का नजारा देखने को मिलता था लेकिन अब महिलाएं कुछ इस तरह का एहसास करते हुए सफर कर रही हैं जैसे वही ट्रेन को चला रही हों। यह अनोखा अनुभव पुरुष यात्रियों के लिए संभव नहीं है क्योंकि दिल्ली मेट्रो का पहला कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस कारण बिना चालक वाली मेट्रो के रोमांचक सफर का असली अनुभव महिलाओं को मिल रहा है। महिलाएं इस सफर के अनुभव को सहेजने के लिए सेल्फी ले रही हैं। अपने बच्चों को भी चालक वाली जगह पर खड़े कर सफर का नजारा दिखा रही हैं। मौजूदा समय में दिल्ली मेट्रो की मजेंटा और पिंक लाइन पर चलने वाली लगभग सभी ट्रेनों से ऑपरेटर का केबिन हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि आने वाले

समय में मेट्रो के अन्य कॉरिडोर पर भी बिना चालक वाली ट्रेनें ही दौड़ेंगी। चालक रहित ट्रेनों का बेड़ा चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। अभी मजेंटा और पिंक लाइन पर चालक रहित ट्रेनें संचालित हो रही हैं। इसमें पहले तो ट्रेन ऑपरेटर तैनात किए जाते थे लेकिन अब पूरी तरह स्वचालित ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके लिए ट्रेन के कोच से चालक के केबिन को भी हटा दिया गया है। इससे यात्रियों को बैठने के लिए और जगह मिलेगी। चालक रहित ट्रेन संचालन पहली बार दिसंबर 2020 में मजेंटा लाइन (जनकपुरी पश्चिम से बॉटेनिकल गार्डन) पर शुरू किया गया था। बाद में नवंबर 2021 में पिंक लाइन (मजलिस पार्क से शिव विहार) पर इस तकनीक को पेश किया गया। दिल्ली मेट्रो का पूरी तरह से स्वचालित नेटवर्क मौजूदा समय 100 किमी के करीब का है। यह मजेंटा और पिंक दोनों लाइनों पर उपलब्ध है। अधिकारियों का दावा है कि यह भारत में दिल्ली मेट्रो एकमात्र चालक रहित ट्रेन संचालन नेटवर्क बन गया है। मजेंटा लाइन पर चालक रहित ट्रेनों की शुरुआत के साथ डीएमआरसी दुनिया के उन सात प्रतिशत मेट्रो नेटवर्क की एलीट लीग में शामिल है जो बिना चालक के चल सकते हैं। स्वचालित मेट्रो ट्रेनों से मानवीय हस्तक्षेप और मानवीय त्रुटियां कम होंगी।

हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता... अमित शाह

नई दिल्ली। भारत में आतंकवाद के पतन के कगार पर होने की बात दोहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने संबोधन में कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। पहलगाम नरसंहार और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे वापस लेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की उदार नीतियों और तुष्टिकरण के रवैये ने देश में आतंकवाद को पनपने और फलने-फूलने का मौका दिया। सौभाग्य से, अब हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो केवल दस्तावेजों पर निर्भर रहने के बजाय निर्णायक कार्रवाई करता है, ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के इस आकलन की आलोचना करते हुए कि 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकवादियों से पाकिस्तान का कोई ठोस संबंध नहीं है, गृह मंत्री ने कहा, -चिदंबरम साहब ने कल कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता कि ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक था।

चिदंबरम साहब यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या 1965 और 1971 के युद्ध निर्णायक थे। अगर वे निर्णायक थे, तो आतंकवाद क्यों फैलता रहा? गृह मंत्री ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के 2008 के उस बयान का भी ज़िक्र किया जिसमें उन्होंने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों में आरएसएस के शामिल होने की संभावना जताई थी। शाह ने पूछा कि हमारी एजेंसियों को इस बात के सबूत मिले हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान से थे। लेकिन उनके (चिदंबरम के) गृह मंत्री रहते हुए अफ़ज़ल गुरु को फांसी नहीं दी गई... मुंबई आतंकी हमले के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा था कि आरएसएस ने इसे अंजाम दिया है।

वे किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? वे क्या कहना चाह रहे हैं? मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में क्या कहा? एक हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। इस देश में सभी आतंकवादियों का एक ही धर्म है। यह साबित हो चुका है। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद शब्द फैलाने का गंदा काम किया। अब सब कुछ स्पष्ट है, और कांग्रेस को इसके परिणाम भुगतने होंगे। पाकिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ने के बजाय, भारत के लोगों पर आरोप क्यों लगाया गया? शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करने वाले पी चिदंबरम ने कुछ समय पहले पहलगाम हमले के पीछे के हमलावरों के बारे में भी कहा था कि क्या सबूत है कि वे पाकिस्तान से आए थे?... क्या वह (पी चिदंबरम) भारतीय लोगों को आतंकवादी कह रहे थे? कांग्रेस को उनसे ये सवाल पूछने चाहिए... आतंकवाद को खत्म करने में अपनी विफलता को छिपाने के लिए उन्होंने भगवा आतंकवाद जैसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की... आज सच्चाई लोगों के सामने आ गई है।

करंट लगने से भाई-बहन की दर्दनाक मौत, पिता अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में अपने घर पर बिजली का करंट लग जाने से एक युवक और उसकी बहन की मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से झुलसे उनके बुजुर्ग पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान वेल्डिंग का काम करने वाले विवेक (26) और उसकी बहन अंजू (28) के रूप में हुई है, जबकि उनके पिता कालीचरण (65) का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अंजू की तीन महीने पहले ही शादी हुई थी। उन्होंने बताया कि बेगमपुर थाने में बुधवार रात 10 बजकर 56 मिनट पर पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को सूचना मिली। खुद को पीड़ितों का पड़ोसी बताते हुए फोन करने वाले अभिषेक ने कहा, ''यहां लाइट कटवा दो, तीन आदमी चिपके हुए हैं। पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और वहां अभिषेक ने उन्हें बताया कि स्थानीय लोगों ने बिजली से झुलसे तीनों लोगों को अग्रसेन अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस उपायुक्त (रोहिणी) राजीव रंजन ने बताया कि अपराध शाखा की एक टीम और 'नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया, ''प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 50 वर्ग गज के भूखंड पर बने इस घर में बिजली के तार खुले और असुरक्षित तरीके से लगाए गए थे और सीढ़ियों पर लगी लोहे की ग्रिल के चारों ओर तार लपेटे गए हैं।

संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर शाब्दिक महासंग्राम- पीएम नरेन्द्र मोदी बनाम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी-ट्रंप के नाम की भी गूंज

वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चल रहे मानसून सत्र को पूरी दुनियाँ लाइव देख रही है जिसमें पिछले कुछ सत्रों की तरह इस सत्र में भी ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप का 29 बार सीजफायर करने का दावा व बिहार वोटर वेरीफिकेशन इत्यादि मुद्दों पर हंगामें की वजह से कामकाज ठप पड़ा था। आखिर सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने की बात मानी और संसद के दोनों सदनों में 16-16 घंटे की बहस 28-29 जुलाई 2025 को देर रात्रि समाप्त हुई। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र दोनों दिन पूरी बहस को टेलीविजन के माध्यम से कवर किया तो पाया के सभी पक्षकारों ने तर्क वितर्क बहुत ही शानदार किया परंतु विशेष रूप से रेखांकित करने वाली बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व प्रियंका गांधी तथा पीएम मोदी रहे। जिसमें मैंने महसूस किया कि तीन बातों से मैं और शायद जनता भी संतुष्ट नहीं हुई होगी (1) यह कि ट्रंप की गूंज इस मामले में संसद के दोनों सदनों में हुई जो 29 बार कह चुके है कि सीजफायर उन्होंने करवाया है।(2) मुद्दा कि भारत इतनी आसानी से पाक डीजीएमओ का निवेदन कैसे मान सकता है, जबकि पूर्ण विपक्ष, सरकार के साथ खड़ा था।और (3) अंतिम बात जब इतनी 32 घंटे की बहसबाजी तर्कवितर्क हुए तो फिर विभिन्न पार्टियों के सांसद 7 डेलिगेशन बनाकर पूरी दुनियाँ में क्या समझाने गए थे। हालांकि विपक्ष के सभी वक्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब माननीय पीएम ने 29 जुलाई 2025 को अंत में देर रात्रि एक घंटा 22 मिनट का समय लेकर पूरे सवालों के जवाब दिए,फिर भी मेरा मानना है कि यह तीन प्रश्न मेरे और जनता के मन में क्लियर नहीं हुए हैं इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पर 32 घंटे की बहस में, पूरी दुनियाँ में घूमे सभी पार्टियों के 7 डेलिगेशन व ट्रंप द्वारा सीजफायर करवाने के 29 बार बयान पर जवाब/खंडन नहीं आया जो रेखांकित करने वाली बात है। साथियों बात अगर हम दिनांक 29 जुलाई 2025 को देर रात्रि समाप्त हुए 32 घंटे के ऑपरेशन सिंदूर पर शाब्दिक महासंग्राम में नेता प्रतिपक्ष व अनेक सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों की करें तो,नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहलगाम में हुआ हमला बर्बर और निर्दयी था,जो पूरी तरह पाक प्रायोजित था। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने भारत की सेना और चुनी हुई सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहने की प्रतिबद्धता जताई थी। हमें गर्व है कि एक विपक्ष के तौर पर हम उस तरह एकजुट रहे जैसा हमें होना चाहिए था। ट्रम्प ने 29 बार कहा है कि हमने सीजफायर करवाया। अगर दम है तो पीएम यहां सदन में यह बोल दें कि वह झूठ बोल रहे हैं।अगर वह झूठ है तो पीएम यहां बोल दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पीएम में हिम्मत है तो वो बोल देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में बहस के दौरान सरकार पर पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आतंकी हमले की जिम्मेदारी को लेकर कहा कि किसी का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? अपने भाषण में उनका निशाना रक्षा,गृहमंत्री पर था। उन्होंने कहा 2008 में आतंकी हमला हुआ। राज्य के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ। देश के गृहमंत्री ने इस्तीफा दिया, क्या इस सरकार में किसी काइस्तीफा हुआ ? क्या सेना प्रमुख,क्या इंटेलीजेंस प्रमुख ने इस्तीफा दिया? क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी तक नहीं ली? सांसद गौरव गोगोई ने भी सोमवार को लोकसभा में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि रक्षा मंत्री ने बहुत सारी जानकारी दी लेकिन रक्षामंत्री के रूप में उन्होंने उल्लेख नहीं किया कि कैसे पाक से आतंकवादी पहलगाम पहुंचे और 26 लोगों को मार डाला।गोगोई ने कहा, पूरा देश और विपक्ष पीएम का समर्थन कर रहा था। अचानक 10 मई को हमें पता चला कि युद्ध विराम हो गया है। क्यों? हम पीएम से जानना चाहते थे कि अगर पाकिस्तान घुटने टेकने को तैयार था तो आप रुके क्यों और किसके सामने आत्मसमर्पण किया? अमेरिकी राष्ट्रपति 26 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। साथियों बात अगर हम माननीय पीएम ने देररात्रि तक ऑपरेशन सिंदूर पर 1 घंटा 22 मिनट में सभी प्रश्नों का जवाब देने की करें तो,पहली बार इन विवरणों का खुलासा करते हुए,उन्होंने कहा,हमने पहले दिन से ही कहा था कि हमारी कार्रवाई कोई उग्र कार्रवाई नहीं है। दुनियाँ के किसी भी नेता ने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। 9 मई की रात को,अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मुझसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने एक घंटे तक कोशिश की, लेकिन मैं सुरक्षा बलों के साथ बैठक में व्यस्त था।

जब मैंने उन्हें वापस बुलाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि पाक एक बड़े हमले की योजना बना रहा है।मेरा जवाब था कि अगर पाक की यही मंशा है,तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्होंने जोर देकर कहा,अगर पाक हमला करता है, तो हम बड़े हमले से जवाब देंगे। मैंने कहा था, हम गोली का जवाब तोप के गोले से देंगे। 10 मई को हमने पाक की सैन्य ताकत को नष्ट कर दिया।

यह हमारा जवाब और हमारा संकल्प था। यहां तक कि पाक भी अब समझता है कि भारत का हर जवाब पिछले जवाब से बड़ा है। वह जानता है कि अगर भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है। मैं लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं,ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 मई को पाक और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद, भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। जब पाकिस्तान ने आतंकवादियों का बचाव करने के लिए कदम उठाया, तभी भारतीय सशस्त्र बलों ने उसे ऐसा सबक सिखाया जिसे वह वर्षों तक याद रखेगा। साथियों बात अगर हम माननीय पीएम व नेता प्रतिपक्ष के सवालों जवाबोंकी करें तो, नेता प्रतिपक्ष का आरोप - इन्होंने ट्रंप के कहने पर सरेंडर कर दिया,पुम ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में विशेष चर्चा के दौरान अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने नेता विपक्ष के आरोपों का एक-एक करके करारा जवाब दिया.मोदी ने सदन में एक घंटा 24 मिनट तक भाषण दिया, इस दौरान उन्होंने ट्रंप के कहने पर सरेंडर, संघर्षविराम, कमजोर विदेश नीति, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी जैसे तमाम आरोपों का चुन-चुनकर जवाब दिया।मोदी का जवाब - जब हमने पाक को घुटनों पर ला दिया, तब पाक के डीजीएमओ ने फोन करके कहा- अब बस करो।

दुनियाँ के किसी नेता ने हमसे ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ऑपरेशन के दौरान मुझसे बात करने की कोशिश की, मैं फोन नहीं उठा पाया. बाद में बात हुई तो उन्होंने बताया कि पाक बहुत बड़ा हमला करने वाला है. मेरा जवाब था- अगर पाक का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। आरोप - इन्होंने 22 मिनट बाद पाक को बता दिया कि हम लड़ना नहीं चाहते.पीएम का जवाब - हमने पाक को बता दिया 5 कर दिया।राहुल गांधी का दावा - इंडिया गठबंधन के सभी नेता सरकार के साथ खड़े रहे.पीएम मोदी का जवाब - दुनिया के देशों ने हमारा समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला, दुर्भाग्य है. हमले के तीन-चार दिन के बाद ही उछलने लगे और कहने लगे- कहां गई 56 इंच की छाती, इन्हें लगा कि हमने इन्हें गिरा दिया. राहुल गांधी - इनकी विदेश नीति फेल है, दुनिया के किसी देश ने पाकिस्तान की आलोचना नहीं की.पीएम मोदी - दुनिया के किसी देश ने हमें अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है.राहुल गांधी - मुनीर ट्रंप के साथ लंच कर रहा है, अब ये न्यू नॉर्मल है.पीएम मोदी - अब (पाकिस्तान) भारत पर हमला करेगा तो घुस के मारेंगे, ये है न्यू नॉर्मल। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि संसदमें ऑपरेशन सिंदूर पर शाब्दिक महासंग्राम- पीएम नरेन्द्र मोदी बनाम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी-ट्रंप के नाम की भी गूंज ऑपरेशन सिंदूर पर बहस संसद से लाइव- भारत सहित पूरी दुनियाँ ने देखी-ट्रंप का 29 बार का बयान व पाक डीजीएमओ के सीजफायर निवेदन पर युद्ध विराम तर्क पर क्या देश संतुष्ट हुआ? ऑपरेशन सिंदूर पर 32 घंटे की बहस में, पूरी दुनियाँ में घूमे सभी पार्टियों के 7 डेलिगेशन व ट्रंप द्वारा सीजफायर करवाने के 29 बार बयान पर जवाब/खंडन नहीं आया जो रेखांकित करने वाली बात है।

सम्पादकीय...

भाषायी सहिष्णुता की अपील

आमची मराठी बोध को लेकर जारी सियासी खींचतान के बीच आए राज्यपाल के बयान को लेकर विवाद नहीं होता तो ही आश्चर्य होता। मराठी स्वाभिमान के बहाने हिंदीभाषियों से हिंसा का समर्थक रही महाराष्ट्र नव निर्माण सेना वाली मनसे हो या फिर शिवसेना-उद्धव ठाकरे, दोनों के नेता राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के विरोध में उतर आए हैं। शिवसेना-उद्धव के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है कि मराठी महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या भूटान में बोली जाएगी। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा है कि राज्यपाल को मराठी स्वाभिमान और मराठी भाषा के अपमान में अंतर समझना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन भले ही तमिलभाषी हों, लेकिन मराठी गौरवबोध के बहाने जारी भाषा विवाद में हस्तक्षेप करके उन्होंने एक तरह से अपने दायित्वबोध को ही जाहिर किया है। तमिलनाडु के कोयंबटूर से दो बार लोकसभा सदस्य रहे राधाकृष्णन आपसी बातचीत में मानते रहे हैं कि राजनीति में अखिल भारतीय व्यक्ति के लिए हिंदी का सहयोग जरूरी है। इन पंक्तियों के लेखक से कई बार उन्होंने हिंदी सिखाने की अपील की है। यह बात और है कि हिंदी के कुछ शब्दों के अलावा कुछ ज्यादा नहीं सीख पाए। तमिलनाडु के राजनीतिक हलकों में उन्हें तमिल मोदी कहा जाता रहा है। तमिलनाडु की राजनीति हिंदी के कट्टर विरोध के लिए जानी जाती रही है। 1968 में तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ हिंसक आंदोलन हो चुका है। राधाकृष्णन ने उस आंदोलन की हिंसक तपिश को महसूस किया है। इसके बावजूद हिंदी सीखना उनकी चाहत रही है। हिंदी विरोध की आंच में पले-बढ़े तमिलनाडु की एक पूरी पीढ़ी आपसी बातचीत में मानती है कि उसने क्या खोया है। वह पीढ़ी अब प्रौढ़ावस्था के उत्तरार्ध की ओर बढ़ रही है। वह मानती है कि अगर हिंदी विरोध की आंच में झुलसने का उसे अंदाजा होता तो हिंदी के विरोध में वह अपनी जिंदगी और अपने सपनों को होम नहीं करती। राज्यपाल ने वैसे कुछ ऐसा नहीं बोला है, जिसे तूल दिया जा सके। उन्होंने कहा है कि किसी को पीटने के बाद क्या वह तत्काल मराठी बोलने लगेगा। निश्चित तौर पर इसका जवाब ना ही है। सीपी राधाकृष्णन 1998 और 1999 में लगातार दो बार कोयंबटूर से चुने गए थे। उन दिनों वे तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। उसी दौर की एक घटना का जिक्र उन्होंने अपने बयान में किया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि एक बार वे तमिलनाडु में कहीं जा रहे थे तो तमिल न बोलने के चलते कुछ हिंदीभाषी लोगों के साथ स्थानीय भाषा आंदोलनकारी मारपीट कर रहे थे। जिसके लिए उन्होंने हिंदीभाषियों से माफी मांगी और तमिल बोलने की जिद करने वाले लोगों से कहा था कि क्या उनके इसी पिट जाने के बाद कोई तत्काल तमिल बोल पाएगा। भारत की हर भाषा का सम्मान हो, हर भाषा को बोलने वालों का सम्मान हो, इस सोच को बढ़ावा देने की जरूरत है। भारत की हर भाषा एक-दूसरे से जुड़ी है। भारत की भाषाएं आपस में बहनें हैं। इनके बहनापा को बढ़ावा देने की जरूरत है। कोई भाषा श्रेष्ठ है या कोई भाषा कमजोर है, इसकी तुलना भी बेमानी है। बहुभाषी भारत में एक कहावत पूरी शिद्दत से कही जाती है कि कोस-कोस पर पानी बदले, तीन कोस पर बानी। इसका आशय साफ है कि कुछ ही दूरी पर भाषा का स्वरूप बदल जाता है। लेकिन क्या व्यक्ति इसका व्यवहार करना छोड़ देता है,क्या कुछ दूरी पर बदली भाषा से वह घृणा करने लगता है। भाषाओं की दुनिया किसी एक की जागीर नहीं है कि बाड़ लगाकर उन्हें रोक दिया जाएगा, भाषाओं का समान नदी के पानी की तरह भी नहीं है कि उनके किनारों को बांध बनाकर रोक दिया जाएगा और उसके पानी को नियंत्रित कर लिया जाएगा। दरअसल भाषाएं नदी के प्रवाह की तरह हैं। जिस तरह हर नदी का अपना प्रवाह है, उसके प्रवाह की अपनी ध्वनि है, कुछ ऐसा ही हाल हर भाषा का है। लेकिन तमिल हो या मराठी, उन्हें बेहतर मानने और बाकी भाषाओं को कमतर समझने की सोच सही नहीं है। हर भाषा उसे बोलने वाले मूल व्यक्ति के लिए उसकी अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ माध्यम है। राज्यपाल के बयान का मकसद भाषाओं की दुनिया को इसी खूबसूरती से परिचित करना और उनके गौरवबोध से लोगों का परिचय कराना है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाए या तमिलनाडु में तमिल का व्यवहार बाकी भाषाओं की तुलना में बेहतर हो, इससे भला किसी को क्यों इनकार होगा। लेकिन मराठी और तमिल को बेहतर बताने और हिंदी को कमतर बताने की सोच को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हिंदी ही क्यों, बाकी भारतीय भाषाओं को कमतर बताना भी उचित नहीं होगा। भाषा को लेकर गौरवबोध होना तो ठीक है, लेकिन अपनी भाषा के गौरवबोध को कथित तौर पर स्थापित करने के लिए हिंसा का सहारा लेना या जबरदस्ती करना उचित नहीं है। ऐसा करना एक तरह से कानून-व्यवस्था का मामला बन जाता है। ऐसे में राज्यपाल का यह कहना उचित ही है कि कानून-व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो निवेशक राज्य में आने से बचेंगे, निवेश घटेगा तो राज्य में उत्पादक इकाइयां कम होंगी, इससे रोजगार घटेगा और राज्य का राजस्व भी। भाषा की राजनीति को इन तथ्यों को भी समझना होगा। उसे देखना होगा कि भाषा के प्रति प्यार और स्नेह अराजकता का जरिया ना बने। भाषा को लेकर आक्रामक राजनीति करने वाले दलों को भी समझना होगा कि भाषाई स्वाभिमान के नाम पर होने वाली जबरदस्ती अंततः दूसरे पक्ष को भी उकसाती है। सोचिए, अगर हर भाषाभाषी अराजक ढंग से अपने भाषायी गौरवबोध को उभारने और उसे अभिव्यक्ति देने लगे तो क्या होगा ? अराजकता का तीव्र विस्फोट होगा और उससे अंततः राष्ट्र की नींव में सुराखें बनने लगेंगी। जिसकी बुनियाद पर राष्ट्र का खड़ा रह पाना कठिन होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान को इन संदर्भों में भी देखा और समझा जाना चाहिए। राज्यपाल ने ठीक ही कहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा पर गर्व भी करना चाहिए। इसे लेकर कोई समझौता भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम किसी और की मातृभाषा से नफरत करें। भाषाओं के नाम पर अराजक होने की बजाय जरूरत इस बात की है कि हम एक-दूसरे की भाषा ही नहीं, उसके समूचे अस्तित्व के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। तुच्छ और तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए भाषा के नाम पर सहिष्णुता का यह पुल एक बार टूटा तो उसे फिर से स्थापित कर पाना बेहद कठिन होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान को इन्हीं संदर्भों में देखा, परखा और समझा जाना चाहिए।

ऑपरेशन सिन्दूर और संसद

ऑपरेशन सिन्दूर पर संसद के दोनों सदनों में चली लम्बी बहस का निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प असत्य या झूठ बोल रहे हैं। अब तक ट्रम्प 29 बार यह कह चुके हैं कि उनकी मध्यस्थता के कारण ही भारत-पाकिस्तान में हुई लड़ाई पर विराम लगाया गया। हर देशवासी जानता है कि विगत 7 मई से लेकर 10 मई तक दोनों देशों के बीच सैनिक संघर्ष हुआ था। यह युद्ध चल ही रहा था कि ट्रम्प साहब ने 10 मई की शाम को यह ट्वीट कर दिया कि भारत व पाकिस्तान दोनों युद्ध पर विराम लगाने के लिए राजी हो गये हैं। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही भारत की ओर से विदेश सचिव श्री विक्रम मिसरी ने एक प्रेस कान्फ्रैंस करके युद्ध विराम की घोषणा यह कहते हुए की कि पाकिस्तान के आला सैनिक अफसर (डीजीएमओ) ने इसकी याचना भारत के समकक्ष सैनिक अफसर से की थी। मगर यह भी हकीकत है कि ट्रम्प ने युद्ध विराम की घोषणा भारत की घोषणा से पहले ही कर दी थी। लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे चली बहस में युद्ध विराम का मुद्दा ही सबसे ज्यादा संजीदा था।

अतः प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में दिये गये अपने बयान से इसकी धुंध को छांटा और घोषणा की कि विश्व के किसी भी नेता के हस्तक्षेप की वजह से युद्ध विराम नहीं हुआ, बल्कि भारत ने पाकिस्तान की याचना को स्वीकार किया है। विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने बयान से इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर लिया था और कहा था कि यह युद्ध अकेले पाकिस्तान ने नहीं लड़ा, बल्कि चीन ने भी पाकिस्तान के कन्धे पर बन्दूक रखकर लड़ा है। कूटनीति में विपक्ष के सांसद होने की वजह से राहुल गांधी ऐसा बयान दे सकते हैं परन्तु सरकार में बैठा कोई भी जिम्मेदार मन्त्री इसका समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि सरकार देश की सुरक्षा और इसकी संप्रभुता की रक्षक होती है। इसी केन्द्र में रखकर ही कोई भी सरकार द्विपक्षीय मामलों में अपना नपा-तुला पक्ष रखती है। जाहिर है कि जब पाकिस्तान अपनी तरफ से भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है तो सरकार ने उसी का नाम लेकर ऑपरेशन सिन्दूर आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ चलाया था। लोकतन्त्र में विपक्ष को यह खुली छूट होती है कि वह सरकार से तीखे से तीखे सवाल पूछे और हर कोशिश करे कि सरकार को बेनकाब किया जाये। हम यदि पिछले ताजा राजनैतिक इतिहास पर नजर डालें तो पायेंगे कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो वह क्या और कैसे पैंतरे कांग्रेस सरकारों को घेरने के लिए बदला करती थी। 1971 में जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सोवियत संघ से 20 वर्षीय सैनिक सन्धि की थी तो भाजपा (जनसंघ) के नेता स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनसभा करके इसकी प्रतियां जलाई थीं। ऐसा ही 1972 में पाकिस्तान के साथ हुए शिमला समझौते के साथ भी किया गया था परन्तु जब 1998 व 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमन्त्री 2004 तक बने तो उन्होंने लोकसभा में ही स्वीकार किया कि विपक्ष में रहते हुए आपको बहुत छूट होती है मगर सरकार में आने पर पूरे देश की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। श्री वाजपेयी के इस बयान ने साफ कर दिया था कि विपक्षी दलों को अपनी राजनीति चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऑपरेशन सिन्दूर पर बहस का स्तर ठीक-ठाक ही कहा जायेगा। मगर यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की ओर से इस सवाल का जवाब नहीं आया कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे।

यह सवाल सीधे हमारी सेनाओं के मनोबल से जुड़ा हुआ है और सेना की रणनीति का हिस्सा है। प्रश्न यह है कि क्या हम ऑपरेशन सिन्दूर में सफल रहे? इसका उत्तर है कि शत-प्रतिशत रूप से हमारी विजय हुई है क्योंकि हमने केवल चार दिनों के भीतर ही पाकिस्तान के 11 हवाई सैनिक अड्डों को तहस-नहस कर डाला और आतंकवादियों के नौ ठिकानों को जमींदोज कर डाला। प्रधानमन्त्री ने जब लोकसभा में यह कहा कि पाकिस्तान की तरफ से एक हजार ड्रोनों और मिसाइलों से हमला किया गया था और भारतीय सेनाओं ने इन सभी को हवा में ही नष्ट करके पाकिस्तान के 11 हवाई सैनिक अड्डों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान की वायुसेना सुरक्षा प्रणाली को नाकाम बना दिया था तो प्रत्येक भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा उठ गया था। अतः विपक्ष की हताहत लड़ाकू विमानों की संख्या जानने की जिद राष्ट्रहितों के विपरीत है। इस बहस में पाकिस्तान के साथ 1960 में हुए सिन्धु नदी जल समझौते का भी मुद्दा उठा। प्रधानमन्त्री मोदी ने इस पर छायी हुई धुंध को भी साफ किया और कहा कि भारत ने यह समझौता इसलिए बरतरफ कर दिया है क्योंकि यह राष्ट्रहितों के खिलाफ है। इसमें तीन नदियों का ही पानी पाकिस्तान को 80 प्रतिशत देने का प्रावधान है। श्री मोदी ने भरी संसद में इसका खुलासा करते हुए जो तथ्य सामने रखे उससे कोई भी देशवासी आश्चर्य में पड़ सकता। मगर अब 21वीं सदी चल रही है और भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में आतंकवाद की वजह से गुणात्मक परिवर्तन आ चुका है तथा वैश्विक परिदृश्य भी पूरी तरह बदल चुका है। बदली हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की रोशनी में ही हमें अपने राष्ट्रीय सुरक्षित रखने हैं, वर्ना क्या मजाल है कि पाकिस्तान जैसा नामुराद और नाजायज मुल्क हमें आतंकवाद का शिकार बनाये। भारत जैसे लोकतान्त्रिक राष्ट्र को सभी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही अपना रास्ता तय करना होगा। हमें इस मोर्चे पर दूरगामी परिणाम देने वाले कदम राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करते हुए उठाने होंगे। जहां तक चीन व पाकिस्तान की गलबहियों का मुद्दा है तो यह काम आज ही नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 25 सालों में दोनों देशों के बीच चल रहे घटनाक्रम का नतीजा है जैसा कि विदेश मन्त्री श्री एस. जयशंकर ने राज्यसभा में बताया।

ट्रंप का टैरिफ, पेनल्टी हमला और पाकिस्तान से तेल खरीदने की नसीहत- भारत को सटीक जवाब देने की जरूरत

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार भारत पर टैरिफ और पेनल्टी अर्थात जुर्माने का हमला कर ही दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यह भूल गए कि भारतीयों ने उनके देश के विकास में कितनी अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप ने भारत पर सिर्फ 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की ही घोषणा नहीं की है बल्कि भारत की लॉन्ग टर्म ट्रेड प्रैक्टिस और वैश्विक नीति पर सवाल उठाने की कोशिश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत द्वारा रूस से हथियार और तेल खरीदने का जिक्र करते हुए भारत पर पेनल्टी के रूप में अतिरिक्त जुर्माना लगाने की भी घोषणा की है। भारत का ब्रिक्स संगठन का महत्वपूर्ण देश होना भी अमेरिका को खटक रहा है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश और भारतीयों के महत्व को किनारे करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर बताया कि यह टैरिफ एक अगस्त से लागू होगा। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित 25 प्रतिशत टैरिफ पहले घोषित 10 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त होगा या उसी में समाहित होगा। क्योंकि ट्रंप ने इससे पहले 2 अप्रैल को भारत सहित कई देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी,जिसे पहले 90 दिनों तक और फिर बाद में एक अगस्त तक के लिए टाल दिया गया था। ट्रंप ने टैरिफ का यह ऐलान एकतरफा तरीके से करके अपने इरादों को जाहिर कर दिया है। जबकि टैरिफ और व्यापारिक रिश्तों पर भारत और अमेरिका के अधिकारी पिछले कई महीनों से चर्चा कर रहे हैं और छठे दौर की बातचीत के लिए अमेरिकी दल के 25 अगस्त को भारत आने का कार्यक्रम पहले ही तय हो चुका है। भारत सरकार ने ट्रंप के इस टैरिफ वॉर पर फिलहाल संतुलित प्रतिक्रिया ही दी है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी कर कहा, सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार के विषय पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का संज्ञान लिया है। सरकार इसके संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रही है। भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। हम इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत के बयान में आगे कहा गया है, सरकार भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के कल्याण और हितों को सर्वोच्च महत्व देती है। राष्ट्रहित में सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जैसा कि हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुए समझौते सहित अन्य व्यापार समझौतों में किया गया है। भारत की इस संतुलित प्रतिक्रिया को कूटनीतिक और वैश्विक रिश्तों के लिहाज से भले ही महत्वपूर्ण माना जा रहा हो लेकिन ट्रंप के रुख को देखते हुए भारत पर उसी भाषा में जवाब देने का दबाव भी बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि भारत पर टैरिफ और जुर्माना लगाने की घोषणा के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल के एक बड़े भंडार को विकसित करने की भी घोषणा कर दी है।

भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं

यह अफसोस की बात है कि देश में फिर भाषा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अंग्रेजी बनाम हिन्दी, हिन्दी बनाम मराठी, हिन्दी बनाम कन्नड़, हिन्दी बनाम तमिल। ममता बनर्जी का कहना है कि वह बंगला के लिए मरने को तैयार हैं। ऐसे विवाद अनावश्यक है क्योंकि किसी भी भाषा को यहां खतरा नहीं है और न ही ममता जी को अपनी जान देने की ही जरूरत पड़ेगी। सारी भाषाओं का विकास होना चाहिए, पर यहां तो अनावश्यक लड़ाई-झगड़े शुरू हो गए हैं। इस विवाद का सबसे बदसूरत चेहरा हमने मुम्बई में देखा जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों ने उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया जो मराठी नहीं बोल सकते। मुम्बई में सारे देश से लोग बसते हैं। केवल 35-36 प्रतिशत लोगों ने ही मराठी को अपनी मातृभाषा घोषित किया था। हिन्दी बोलने वाले भी लगभग बराबर हैं। जिसे बंबइया भाषा कहा जाता है वह मराठी, हिन्दी, गुजराती और अंग्रेजी की खिचड़ी है। सबको मराठी नहीं आती। क्या अब सब थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाएं? महाराष्ट्र की सरकार ने स्कूलों में पहली से पांचवीं तक तीन भाषाई फार्मूला लागू किया था। मराठी के साथ हिन्दी को अनिवार्य किया, पर बाद में ऐच्छिक कर दिया, पर राजनीतिक जमीन तलाश रही मनसे भड़क उठी कि इससे मराठी अस्मिता को खतरा है। महाराष्ट्र सरकार ने समर्पण कर दिया और आदेश वापिस ले लिया। राजनीतिक तौर पर बेरोजगार राज ठाकरे की अब धमकी है कि वह प्रदेश के उन सब रहने वालों को थप्पड़ मारेंगे जो मराठी में नहीं बोलते। सारे देश से जो कामगार वहां हैं वह कहां जाएंगे? जो पढ़े-लिखे प्रोफेशनल हैं वह क्या करेंगे? जहां तक 'मराठी अस्मिता' का सवाल है, यह दिलचस्प है कि हिन्दी पढ़ने से तो अस्मिता खतरे में पड़ रही है, पर अंग्रेजी पढ़ने से न पहचान और न ही अस्मिता को खतरा है। वहां दसवीं तक अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य है। मराठी को कोई खतरा नहीं? और हिन्दी से मराठी को खतरा किस बात का है? अपनी भाषा के प्रति इतनी असुरक्षा क्यों है? अगर पांचवीं के बाद कोई बच्चा हिन्दी नहीं पढ़ना चाहता तो नहीं पढ़ेगा, झगड़ा किस बात का है? जो मां-बाप अपने बच्चों को अखिल भारतीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करना चाहते हैं वह हिन्दी की जरूरत समझते हैं। अगर आपको मराठी या तमिल या कन्नड़ या किसी और भाषा से प्यार है तो अच्छी बात है,पर हिन्दी से खामखा नफरत प्रदर्शित करने की क्या जरूरत है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी 96 वर्ष के जूलियो रिबेरो, मुम्बई के बारे लिखते हैं, -हिन्दोस्तानी,जैसा मुम्बई के हिन्दी संस्करण को जाना जाता है, को मुम्बई में व्यापक रूप से बोला और समझा जाता है।अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह सब हिन्दी जानते हैं-। इसी प्रकार दक्षिण भारत में हिन्दी के विरोध का मामला है। दक्षिण की अपनी भाषाएं बहुत समृद्ध हैं। तमिल तो संस्कृत से भी प्राचीन है। सब वहां तमिल बोलते हैं, पर बड़ी मात्रा में प्रवासी है। वह क्या करें? देश में आखिर एक तो सम्पर्क भाषा चाहिए जिसे सब समझ सकें। यह हिन्दी के सिवाय और कोई नहीं हो सकती। दुर्भाग्य की बात है कि भाषा भी तनाव का मुद्दा बन गई है, नहीं तो चेन्नई में ही बड़ी संख्या में सीबीएसई और प्राइवेट स्कूलों में बच्चे हिन्दी पढ़ते हैं क्योंकि हिन्दी आपको प्रतिस्पर्धी बनाती है। वहां शोले और दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे जैसी फिल्में महीनों चली थीं जबकि तमिल फिल्म उद्योग खुद बहुत लोकप्रिय है। आजकल दक्षिण की फिल्में उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। यह सिलसिला देश को मजबूत करता है। भावनात्मक एकता बढ़ती है। यह अजीब तर्क है कि अंग्रेजी से कोई खतरा नहीं, हिन्दी से है! जो हिन्दी का विरोध करते हैं उनका कहना है कि 43 प्रतिशत से कम लोगों ने हिन्दी को अपनी मातृभाषा लिखवाया है। यह बात तो सही है, पर क्या कोई और भारतीय भाषा हिन्दी के बराबर भी फटकती है ? बड़ी संख्या उनकी होगी जिन्होंने हिंदी को मातृभाषा नहीं लिखवाया, पर इसे समझते हैं। अंग्रेजी के कई पत्रकार अब बीच-बीच में हिन्दी के शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनती। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने हिन्दी का पक्ष लिया है और कहा -हिन्दी राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। मंत्री नारा लोकेश जो मुख्यमंत्री चन्द्र बाबू नायडू के पुत्र हैं, का पूछना है कि 'हम हिन्दी क्यों न पढ़ें'? यह सब उस प्रदेश से है जिसकी अपनी तेलगू भाषा बहुत प्राचीन और उन्नत है, पर रवैया सकारात्मक है इसलिए अनावश्यक विरोध नहीं कर रहे। सबसे सकारात्मक रवैया केरल सरकार का है। प्राचीन भाषा मलयालम के प्रदेश में सरकार तैयारी कर रही है कि मलयालम और अंग्रेजी के साथ ही पहली से हिन्दी पढ़ाई जाए। यह कदम 45 लाख प्रवासियों के बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रख कर उठाया जा रहा है जो बिहार, उत्तर प्रदेश,उड़ीसा या बंगाल जैसे प्रदेशों से आकर केरल में बसे हैं। यह सही शासन है जो सब की समस्या को समझता है और समाधान निकालने की कोशिश करता है। हैरानी नहीं कि केरल और आंध्र प्रदेश देश के सबसे प्रगतिशील प्रदेशों में से हैं। अफसोस है कि जो मुम्बई में हुआ वह बैंगलोर में भी दोहराया गया। जो कन्नड़ नहीं बोल सकते थे उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की गई जबकि इस शहर की विशेषता ही बाहर से आकर बसे प्रोफेशनल हैं। वह ही इस अराजक शहर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे रहे हैं। जहां देश को हिन्दी की जरूरत है वहां अंग्रेजी के बिना भी गुजारा नहीं। आज के एआई के युग में तो हम बिल्कुल भी अंग्रेजी के बिना नहीं रह सकते। वह हायर एजुकेशन की भाषा है। अंग्रेजी में महारत हमारी सॉफ्ट पॉवर बढ़ाती है। आईटी, मैडिकल, बिसनेस, इंजीनियरिंग में हमारे लोग यहां और विदेश में इतना अच्छा कर रहे हैं तो इसी महारत के कारण है। अमेरिका में मैडिकल और आईटी के क्षेत्रों में हमारे लोग छाए हुए हैं जिससे डोनाल्ड ट्रम्प को तकलीफ हो रही है। हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि -शीघ्र ही देश में अंग्रेजी बोलने वाले शर्म महसूस करेंगे-। मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं क्योंकि यह नहीं होने वाला। उनके अपने मंत्रिमंडल के कई साथियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं।

कइयों के बच्चे वहां बस गए हैं। यह अंग्रेजी में महारत के बिना नहीं हो सकता था। जिनके बच्चे विदेश नहीं भी गए उन्हें भी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। राम मनोहर लोहिया ने अंग्रेजी के खिलाफ अभियान चलाया था, पर हम बहुत आगे आ गए हैं। राजनीतिक कारणों से हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अंग्रेजी आज देश में महत्वकांक्षा और आशा की भाषा बन चुकी है। वास्तव में सारे राजनीतिक वर्ग में अंग्रेजी को लेकर दोगलापन है। ऊपर से वह हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं की बात करेंगे और अंग्रेजी की भर्त्सना करेंगे, पर अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ाएंगे और वह आशा करेंगे कि आक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में एडमिशन मिल जाए या अमेरिका की आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में जगह मिल जाए और अगर हो सके तो बच्चे पश्चिम के देशों में बस भी जाएं। इन्हीं का अनुकरण कमजोर वर्ग भी करने की कोशिश करता है। जो भी कर सकता है वह अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भर्ती करवाता है। ढीली लटकी टाई में स्कूल जाते बच्चे हर शहर या गांव में मिलेंगे। जिन्हें 'कानवेंट' स्कूल कहा जाता है वह भी जगह-जगह उग रहे हैं क्योंकि मां-बाप समझते हैं कि बच्चे अंग्रेजी सीख कर स्मार्ट बन जाएंगे। जो अंग्रेजी का विरोध करते हैं उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि जिन्हें अच्छी नौकरी चाहिए उन्हें आज के भारत में अंग्रेजी की जरूरत क्यों है? मैडिकल जैसा व्यवसाय अंग्रेजी जाने बिना नहीं चल सकता। मध्यप्रदेश में सरकार ने मैडिकल हिन्दी में पढ़ाने की कोशिश की थी। हिन्दी में किताबें छिपाईं, पर एक भी स्टूडेंट हिन्दी में पढ़ने को तैयार नहीं था। ठीक है रूस,चीन,जापान में अपनी भाषा में काम होता है, पर चीन अपने विशेषज्ञ पश्चिमी देशों में भेजता है ताकि वह जानकारी हासिल कर सकें। ऐसा अंग्रेजी में दक्षता बिना नहीं हो सकता। लोगों का अपनी-अपनी भाषा के साथ स्वभाविक लगाव है। हरेक प्रादेशिक भाषा का अपना समृद्ध साहित्य है, अपनी शैली है, बोलचाल है, यहां तक कि अपनी अपनी गाली है। हिन्दी से किसी का टकराव नहीं है।

अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, पर यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। इसके बिना भी गुजारा नहीं। अमित शाह ने खुद बायोकैमिस्ट्री में बीएससी की थी। यह किस भाषा में की होगी? देश के लोग वर्तमान भाषाई स्थिति से समझौता कर चुके हैं इससे छेड़खानी से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। जिस भाषा को देश के लोग चाहेंगे वह खुद उन्नति करेगी। देश के सामने और बहुत सी चुनौतियां हैं जिनसे जूझने की जरूरत है। भाषा तो वैसे भी जोड़ती है, तोड़ती नहीं। याद करिए वह पुराना मधुर गीत, मिले सुर मेरा तुम्हारा जहां भिन्न-भिन्न आवाजों ने मिल कर राष्ट्रीय तराना बना दिया था। यह भारत है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वरुण ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैपलमाना एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2017/00882)

आकांक्षा हाट कार्यक्रम के तृतीय दिवस पर भव्य आयोजन, विधायक रमेश सिंह और जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ

करतूरबा विद्यालय की छात्राओं ने प्रस्तुत किया मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम

जौनपुर ।

जनपद में शासन के निर्देशानुसार 28 जुलाई से 02 अगस्त तक चल रहे आकांक्षा हाट/सम्पूर्णता अभियान के अंतर्गत बुधवार को कार्यक्रम के तृतीय दिवस का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मा0 विधायक शाहगंज रमेश सिंह एवं जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया गया, जहाँ योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों को दी गई। विशेष आकर्षण का केंद्र रहा कस्तूरबा विद्यालय करंजाकला की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें एक छात्रा ने वीर अभिमन्यु की कथा को कविता के रूप में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में मा0 विधायक रमेश सिंह ने कहा कि शासन समाज में समानता और समावेशी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। गरीबों और वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कई जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। उन्होंने बताया कि नीति आयोग द्वारा जनपद के रामपुर और मछलीशहर विकास खण्डों को आकांक्षात्मक विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। विधायक जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं से अब तक वंचित लोगों को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने कहा कि आकांक्षात्मक विकास खण्डों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनके बोलने, सोचने और लिखने की क्षमता को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे अभिभावकों से समन्वय बनाकर बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देशभर में टीबी उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में विद्यालयों में पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु सहजन, नींबू, आंवला आदि के पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हो सके। इस कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, परियोजना निदेशक के.के. पाण्डेय, जिला विकास अधिकारी मीनाक्षी देवी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. अरुण यादव सहित अनेक अधिकारी, शिक्षक, छात्र-छात्राएं और आमजन उपस्थित रहे।

तकनीक और सहभागिता से निपुणता की ओर बढ़ता देवरिया, शिक्षकों की बैठक में गूंजा नवाचार का स्वर

देवरिया।

शिक्षा की नींव को मजबूत करने और बच्चों को निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण पहल करते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), देवरिया के सभागार में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डायट मेंटर्स, एसआरजी, एआरपी और शिक्षा से जुड़े तमाम जिम्मेदारों ने शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डायट प्राचार्य अनिल कुमार सिंह ने कहा कि आज शिक्षा केवल किताबों और कक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि मोबाइल एप्लिकेशन और डिजिटल सामग्री के ज़रिए शिक्षण को दिलचस्प और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि मासिक पाठ्यक्रम विभाजन और आधार संदर्शिकाओं का शत-प्रतिशत अनुपालन हर शिक्षक की जिम्मेदारी है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हर बच्चे तक पाठ्यपुस्तक और अभ्यास पुस्तिका समय से पहुंचे, जिससे सीखने में कोई बाधा न रहे। प्राचार्य सिंह ने एआरपी के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए और कहा कि बच्चों के आकलन में आने वाली समस्याओं की तह तक जाकर समाधान निकालना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षक अगर अपने स्तर पर तकनीकी दक्षता नहीं बढ़ाएंगे तो शिक्षण में गुणवत्ता का दावा सिर्फ़ दिखावा रह जाएगा। बैठक में एसआरजी उपेन्द्र उपाध्याय ने ब्लॉकों से आए एआरपी सदस्यों के समक्ष तकनीकी चुनौतियों और उनके समाधान की दिशा में ठोस प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा कि ÷निपुण प्लस÷ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तकनीक से भागने के बजाय उसका प्रशिक्षण लेकर शिक्षक अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। वहीं कई एआरपी, जैसे केशव प्रताप शाही, सगीर खान, निशेष गुप्त, अखिलेश राय, डॉ. जितेन्द्र, आफताब अहमद, दिलीप गोंड, रामदास, बबलू पाण्डेय, संदीप जायसवाल आदि ने पर्यवेक्षण के दौरान आने वाली जमीनी समस्याओं को साझा किया। बैठक में डायट प्रवक्ता अनिल तिवारी, आदित्य गुप्ता, शीला चतुर्वेदी ने विचार रखते हुए सहायक शिक्षण सामग्री और डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि जब शिक्षण दिलचस्प होगा, तभी बच्चे सीखने में रुचि दिखाएंगे। सतीश मिश्र ने बैठक का संचालन किया और निष्कर्षों को विस्तार से सभी के समक्ष रखा। इस दौरान मारुति नंदन, हीरालाल सिंह, ज्ञानेश यादव, संजय, वशिष्ठ नारायण चौहान, पद्माकर मिश्र, चंदन गुप्त, आदर्श सिंह, राकेश ज्ञानेश, स्तुति, नवीन, मुन्ना अंसारी, सुनील कुमार त्रिपाठी सहित अनेक शिक्षकों और शैक्षिक विशेषज्ञों की सहभागिता रही।

दो बाइकों की टक्कर में एक की मौत

कसया, कुशीनगर। नगरपालिका परिषद कुशीनगर वार्ड नंबर सात सिद्धार्थनगर (मल्लूडीह) में बृहस्पतिवार दोपहर हुई दो बाइकों की टक्कर में एक मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया। प्राप्त सूचना के अनुसार नगरपालिका कुशीनगर के वार्ड नंबर सात सिद्धार्थनगर (मल्लूडीह) में अहमद अली पुत्र मुहम्मद्दीन उम्र 40 वर्ष ग्राम बड़हरागंज कोतवाली पडरौना मोटरसाइकिल से कपड़ा बेचने आए थे। गांव में फेरी करते हुए कपड़ा बेच रहे थे कि विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अहमद अली गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सीएचसी कसया भेजा।हालत गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां जांचोपरांत चिकित्सको ने मृत घोषित कर दिया। कसया थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि सुचना मिली है शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है आगे विधिक कार्रवाई की जायेगी।

1857 के अमर बलिदानियों को नमन- शहीदों की धरती पैना में जिलाधिकारी ने किया श्रद्धांजलि समारोह का नेतृत्व

देवरिया ।

देश की आज़ादी के पहले बिगुल 1857 की क्रांति में बलिदान देने वाले वीरों की स्मृति में मंगलवार को देवरिया की ऐतिहासिक धरती ग्राम पैना एक बार फिर राष्ट्रभक्ति के भावों से सराबोर हो उठी। शहीद द्वार पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने उपस्थित होकर न केवल वीर सपूतों को श्रद्धासुमन अर्पित किए, बल्कि इस स्थल को ऐतिहासिक चेतना और राष्ट्रगौरव का प्रतीक बताया। जिलाधिकारी ने ÷शहीद द्वार÷ का निरीक्षण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की और स्मारक की ऐतिहासिक महत्ता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, पैना गांव की मिट्टी में आज भी 1857 के वीरों की शहादत की खुशबू बसती है। यह द्वार केवल ईंट-पत्थर की संरचना नहीं, बल्कि आज़ादी की पहली चिंगारी में जल उठे उन असंख्य जननायकों की आत्मा का प्रतीक है, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के भारत माता के लिए बलिदान दिया। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों, युवाओं और बच्चों से इस अमूल्य विरासत की रक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इतिहास को केवल किताबों में नहीं, ज़मीन पर ज़िंदा रखने की ज़िम्मेदारी हर नागरिक की है। इस स्मारक का संरक्षण समाज और शासन दोनों की साझी ज़िम्मेदारी है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर, उपजिलाधिकारी बरहज बिपिन द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी अंशुमान श्रीवास्तव समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने माल्यार्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्थानीय स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति और शहीदों के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी ने पूरे वातावरण को भावविभोर कर दिया। ग्रामीणों ने भी वीर शहीदों के सम्मान में अपने घरों पर तिरंगा फहराया और स्मृति द्वार की स्वच्छता में सहयोग किया।

महावीरी अखाड़े में अश्लील गीत व नृत्य पर रोक लगाने की मांग

तमकुही राज कुशीनगर ।

महावीरी अखाडे के मेले में बजरंग बली की मूर्ति स्थापना करके पूजा करते है।बजरंग बली के नारे लगाते है। उनकी मूर्ति के पीछे ऑकेस्ट्रा में अश्लील नृत्य व गीत बजाते है।जो सनातन धर्म के खिलाफ है।इसको तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए प्रशासन से मांग करते हुये भाजपा नेता व पूर्व प्रधान संघ के अध्यक्ष रहे विजय प्रताप सिंह डीएम व एसपी को शिकायत भेजा है। भाजपा नेता व पूर्व प्रधान विजय प्रताप सिंह ने ट्वीट सहित उच्च अधिकारियों को दिए गए शिकायत पत्र में लिखा है कि वर्तमान परिवेश में विरोधियों द्वारा सनातन धर्म पर कड़ा प्रहार किये जा रहे है। प्रतिदिन साजिश रची जा रही है।वही कुछ सनातन धर्म को बदनाम करने के लिये महावीरी अखाड़े जैसे पवित्र अवसर पर आर्केस्ट्रा मांगाकर अश्लील गीत व नृत्य करवाने की तैयारी कर रहे है। आर्केस्ट्रा में अश्लील नृत्य व गाने से कई बार कई स्थानों पर शांति व्यवस्था की भी दिक्कते आई है व कई संगीन घटनाएं भी घट चुकी है।महावीरी अखाडे के मेले में इस प्रकार की फुहड़ता से सनातन धर्म बदनाम हो रहा है।वही आर्केस्ट्रा के दौरान अराजक तत्वों द्वारा महिलाओं के साथ अमर्यादिय टिप्पणी व दुर्व्यवहार भी किया जाता है। इस लिये प्रशासन को मेले के कार्यक्रम में ऑकेस्ट्रा पर पाबंदी या अश्लील नृत्य व गानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग किया है।

उन्होंने यह भी कहा है कि अपना पड़ोसी जिला गोपालगंज में इस कुरीतियों को देखते हुए आर्केस्ट्रा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।केवल पूजा पाठ एवं धर्मिक कार्यक्रम कराने की ही छूट दिया गया है।भाजपा नेता विजय प्रताप सिंह ने स्पष्ट कहा है कि प्रशासन से मांग करते है कि धर्म और आस्था से जुड़े मामले पर गंभीरता से विचार कर अश्लील गाने व नृत्य को प्रतिबंधित करना चाहिये।

जनपद के 11 ब्लाकों में 10, अगस्त से चलेगा फाइलेरिया से बचाव अभियान, 2847 टीमों का हुआ गठन

कुशीनगर।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आगामी 10, अगस्त, 2025 से 28, अगस्त तक जनपद में फाइलेरिया (हाथी पाँव) से बचाव के लिए प्रस्तावित सर्वजन दवा सेवन (एम0डी0ए0) अभियान हेतु प्रथम जनपद स्तरीय बैठक कल सम्पन्न हुयी थी। एम0डी0ए0 अभियान इस वर्ष जनपद के 11 ब्लाकों (रामकोला, कप्तानगंज, मोतीचक, दुदही, नेबुआ नौरंगिया, खड्डा, कुबेरस्थान, विशुनपुरा, सेवरही, तमकुही एवं अरबन पडरौना) में संचालित किया जायेगा जिसमें आशा कार्यकत्रियों द्वारा घर-घर जाकर आयु वर्ग के अनुसार फाइलेरिया रोधी दवा (डी0ई0सी0 एवं एलबेन्डाजाल) अपने सामने खिलायेगी। इस बार लगभग 31 लाख जनसंख्या को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य है। जिस हेतु कुल-2847 टीमें बनायी गयी है। फाइलेरिया एक मच्छर जनित लाईलाज बीमारी है, जिसकी रोकथाम ही इस बीमारी से एक मात्र बचाव है। लगातार 5 वर्षों तक साल भर में एक बार दवा खाने से स्वस्थ व्यक्ति में फाइलेरिया होने की सम्भावना खत्म हो जाती है। (गर्भवती माताओं व एक साल से कम उम्र के बच्चों एवं गम्भीर रुप से बीमार लोगों को यह दवा नही-खिलायी जायेगी।) इस हेतु आशा कार्यकत्रियों को ब्लाक के प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं बी0सी0पी0एम0 द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। दवा सेवन के बाद चक्कर आना, जी मिचलाना जैसी समस्या हो सकती है, लेकिन यह चिन्ता का विषय नहीं है, जिसके शरीर में माइक्रो फाइलेरिया के कृमि होते है जब यह व्यक्ति फाइलेरिया रोधी दवा खाते है तो इस कृमियों के मरने के कारण यह लक्षण दिखायी देते है। एम0डी0ए0 अभियान में सहयोगी विभाग के रुप में (बेसिक शिक्षा विभाग / माध्यमिक शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास / पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश आजिविका मिशन, बाल विकास पुष्टाहार विभाग (आई0सी0डी0एस0), खाद्य एवं रसद विभाग, एन0एस0एस0 एन0सी0सी0 भारत स्काउड एवं गाईड सूचना विभाग, नगर विकास विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) अपना सहयोग प्रदान करेगें। (फाइलेरिया रोधी दवा खाते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह दवा खाली पेट नही खानी है।

ग्राम पंचायत तरया सुजान एवं बोदरवार को नगर पंचायत बनाये जाने तथा कप्तानगंज के सीमा विस्तार से संबंधित पत्र शासन को प्रेषित

कुशीनगर।

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा ए अतितरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के साथ डॉ0 असीम कुमार, मा0 विधायक तमकुहीराज, के पत्र दिनांक-02.02.2024 के क्रम में नगर पंचायत गठन संबंधी शासनादेश में निर्धारित मानकों में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, संस्तुति सहित उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। जिसका क्रम में उप जिलाधिकारी तमकुहीराज से अद्यतन आख्या प्राप्त की गयी उप जिलाधिकारी तमकुहीराज द्वारा प्राप्तआख्या नगर पंचायत गठन संबंधी शासनादेश में दिये गये प्राविधानानुसार आख्या उपलब्ध करायी गयी है। प्रस्तुत आख्या / प्रस्ताव में तहसील तमकुहीराज के ग्राम तरयासुजान, भूलिया, अगरवा, गडहिया पाठक, तरया बैकुण्ठ को सम्मिलि करते हुये राजस्व ग्रामों के समस्त गाटा संख्याओं का दिशावार विवरण, मानचित्र, गाटावार विवरण रूप पत्र-1, रूप पत्र-2. रूप पत्र 3 तथा रूप पत्र- संलग्नक प्रेषित किया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत कप्तानगंज के सीमा विस्तार किये जाने के संबंध में निर्धारित मानकों के क्रम में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, संस्तु सहित उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में उप जिलाधिकारी, कप्तानगंज से आख्या प्राप्त गयी। उप जिलाधिकारी, कप्तागनंज द्वारा नगर पंचायत कप्तानगंज के सीमा विस्तार किये जाने संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नगर क्षेत्र एवं सीमा विस्तारित नगर पंचायत क्षेत्र कुल जनसंख्या 59073 है। प्रस्तावित नगर पंचायत क्षेत्र में तहसील कप्तानगंज के ग्रामसभा बसहिया उर्फ कप्तानगंज, हसनगंज, गजरा, कोटवा, इन्दरपुर, सोहनी, पटखौली, मेहडा, पिए बौलिया, सेमरा तथा मलुकही को नगर पंचायत क्षेत्र में शामिल कर नगर पंचायत कप्तानगंज सीमा विस्तार किये जाने के संबंध में शासनादेश में निर्धारित मानकों के अनुरूप सम्मिलित राजस्व ग्रामों के समस्त गाटा संख्याओ व दिशा विवरण, मानचित्र, गाटावार विवरण, रूपपत्र-1, रूपपत्र-2, रूपपत्र 3 तथा समस्त संलग्नक सहित शासन को प्रेषित कर दी गई है।

बारिश और जलभराव से दिल्ली-एनसीआर त्रस्त, गलियां बनीं झील, सड़कें तालाब

नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। बीती रात करीब 10 बजे से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आधी रात के बाद तक जारी रहा। आज सुबह से कहीं हल्की बारिश की फुहारें तो कहीं झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। नोएडा, गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से रुक-रुककर बारिश हो रही है। बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली वहीं दूसरी तरफ सड़कें तालाब बन गईं। जगह-जगह जलभराव होने से लोगों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। कई इलाकों में सड़कें तालाब तो गलियां और अंडरपास झीलों में तब्दील हो गए। दिल्ली-एनसीआर में रात भर बारिश रुक-रुक कर होती रही। लगातार बारिश के कारण अधिकांश सड़कों के किनारे पानी जमा हो गया है। इससे दिन निकलते ही सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। अलग-अलग इलाकों में वाहनों की कतार देखने को मिल रही है। राजधानी में कल शाम 5 बजे जमकर बादल बरसे। इससे लोगों को उमस से राहत मिली। जगह-जगह लोग बारिश का आनंद लेते भी नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शाम 5:30 बजे तक सफदरजंग मानक केंद्र में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम 32.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार के लिए भी बारिश की संभावना जताई है। 5 अगस्त तक अधिकतम तापमान 33 से 35 के आसपास रहने का अनुमान है। राजधानी में फिर झमाझम बारिश वाला मौसम बन गया है।

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में 4 अगस्त तक कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती है। मौसम विभाग की मानें तो इस हफ्ते दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी देखी जा सकती हैं। गाजियाबाद में देर रात हुई झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़कों पर लबालब पानी भर गया। कई कॉलोनियों व मोहल्लों में लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। आधी रात को हुए जलभराव से लोगों को परेशानी भी हुई। मुख्य मार्गों के अलावा नेहरू नगर, अशोक नगर समेत विभिन्न इलाकों में देर रात कई जगह सड़कों पर घुटने तक पानी भरा हुआ था। बहुमंजिला अपार्टमेंट के बेसमेंट में भी पानी घुस गया। लोगों के पार्किंग में खड़े वाहन पानी में डूब गए। रात करीब 10 बजे से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आधी रात के बाद तक जारी था। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सोसाइटी में रहने वाले लोगों की गाड़ियां पानी में डूब गईं। देर रात हुई बारिश ने बेसमेंट में खड़ी गाड़ियों को डुबो दिया। निवासियों का आरोप है कि उन्होंने लाखों रुपए लगाकर फ्लैट लिया था समिति में हल्की सी बारिश में ही बेसमेंट में पानी भर गया पानी के निकलने की कोई भी बिल्डर की ओर से व्यवस्था नहीं की गई है जिससे उन्हें हर बारिश में परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्री राधा स्काई गार्डन ,महागुण माईवुड्स, गैलेक्सी रॉयल,अजनारा होम्स, सुपरटेक इको विलेज सहित दर्जनों सोसाइटियों में पानी बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण लोगों को अपनी गाड़ियों को निकालने में सुबह कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ऑफिस के लिए तैयार होकर निकले लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। कई निवासियों की आदि गाड़ियां पानी में डूब गई जिससे उनकी गाड़ियों को गद्दियां गीली हो गई।

ट्रंप के 25 फीसदी टैरिफ का रिव्यू कर रहे, भारतीय हितों की रक्षा करेंगे : पीयूष गोयल

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25फीसदी टैरिफ पर भारत सरकार की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा कि भारत आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का 'ब्राइट स्पॉट' है. ट्रंप ने यह भी कहा था कि 'भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है'. गुरुवार को लोकसभा में गोयल ने कहा कि सरकार किसानों, MSMEs और उद्यमियों के हितों की पूरी तरह से रक्षा करेगी. ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने की घोषणा पर उन्होंने कहा, 'हम हर जरूरी कदम उठाएंगे ताकि देश के व्यापारिक हितों को कोई नुकसान न हो.' गोयल ने यह भी गिनाया कि भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, जिससे निर्यात को नई गति मिली है. उन्होंने भरोसा जताया कि भारत वैश्विक व्यापार में मजबूती से खड़ा रहेगा, और सरकार देशहित में हर चुनौती का सामना करेगी. लोकसभा में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 25फीसदी टैरिफ की सरकार गंभीरता से समीक्षा कर रही है. उन्होंने बताया कि भारत-अमेरिका के बीच अब तक चार दौर की बातचीत हो चुकी है. सरकार हर वह कदम उठाएगी जिससे भारत के राष्ट्र हित सुरक्षित रहें. गोयल ने कहा, 'हम अपने किसानों के विकास के लिए पहले भी काम कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे.'

कैबिनेट का फैसला- रेलवे नेटवर्क का विस्तार, किसानों की आय बढ़ाने को बड़ी सौगात

नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छह राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों को कवर करने वाली चार मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 574 किलोमीटर का विस्तार होगा। पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत नियोजित इन परियोजनाओं में इटारसी-नागपुर चौथी लाइन, छत्रपति संभाजीनगर-परभणी दोहरीकरण, अलुआबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन, और डांगोआपोसी-जरोली तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजनाएँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत और देश को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये परियोजनाएँ 2,300 से ज्यादा गाँवों तक कनेक्टिविटी बढ़ाएँगी। रेलवे ने कहा कि लाइन क्षमता में वृद्धि से गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार हैं। वैष्णव ने घोषणा की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के लिए परिव्यय को 1,920 करोड़ रुपये बढ़ाकर 6,520 करोड़ रुपये करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने आगे कहा कि बढ़ी हुई धनराशि का उपयोग 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अनुमोदन में घटक योजना- एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना (आईसीसीवीएआई) और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एफटीएल) के अंतर्गत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए 1,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।

मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपी बरी होने पर भड़के ओवैसी

नई दिल्ली । एनआईए कोर्ट द्वारा सभी सात आरोपियों को बरी किए जाने पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया कि क्या वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे या नहीं? ओवैसी ने कहा कि 17 साल बाद सभी आरोपी बरी हो गए। महाराष्ट्र सरकार ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो क्या अब अगर ऐसा नहीं किया गया, तो ये आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं होगा? उन्होंने आगे कहा कि मालेगांव विस्फोट में मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। इतना खतरनाक विस्फोटक कहां से आया? इसकी जांच क्यों नहीं हुई? असली गुनहगार आज भी खुले घूम रहे हैं। पीड़ितों को न्याय कौन देगा? ओवैसी ने मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार से साफ तौर पर पूछा कि क्या वे इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में जाएंगी या नहीं? अगर नहीं गए, तो यह साफ दिखेगा कि आतंकवाद के मामलों में सिर्फ राजनीतिक फायदा देखा जा रहा है, न्याय नहीं।

जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए- अखिलेश यादव

कोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन जो लोग इतनी बड़ी घटना में शामिल थे, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वहीं इस फैसले पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि इससे फर्क पड़ा है, वे इसे चुनौती देंगे। भाजपा कुछ भी कहे, लेकिन ये कोर्ट का फैसला है और इसे चुनौती दी जा सकती है। निश्चित रूप से दोबारा अपील की जाएगी।

सबूत नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने बरी किया- रामदास अठावले

अदालत ने सभी आरोपियों को बरी किया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो सबूत देना जरूरी होता है।

क्या बोले फडणवीस?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आतंकवाद न कभी भगवा था, न है और न ही कभी होगा। उन्होंने कहा कि अब सच सामने आ गया है।

सीएम योगी ने कांग्रेस से माफी मांगने को कहा

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मालेगांव विस्फोट प्रकरण में सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की सजीव उद्घोषणा है. यह निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है. सीएम योगी ने आगे कहा कि जिसने भगवा आतंकवाद जैसा मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों सनातन आस्थावानों, साधु-संतों और राष्ट्रसेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया है. कांग्रेस को अपने अक्षम्य कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए.

ट्रंप के डेड इकोनॉमी बयान पर राहुल गांधी का समर्थन, बोले- पीएम छोड़ सब जानते हैं

नई दिल्ली ।

राहुल बोले-ट्रम्प ने सही कहा कि इंडियन इकोनॉमी मर चुकी
इसे मोदी ने मारा, ये बात पीएम और वित मंत्री को छोड़कर सबको पता है

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी (मृत अर्थव्यवस्था) बताने पर कहा- मुझे खुशी हुई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैक्ट बताया है। राहुल ने गुरुवार को कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा ने अडाणी की मदद के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। ट्रम्प सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। राहुल का यह बयान ट्रम्प के उस बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रूस और भारत अपनी डेड इकोनॉमी को कैसे संभालते हैं।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी- अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर जो कहा, उसे सबने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें बदले में यही मिलता है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर- यह हमारे लिए बहुत गंभीर मामला है। 25फीसदी टैरिफ के साथ रूस से तेल और गैस खरीदने पर जुर्माना जुड़ सकता है, जिससे यह 35-45फीसदी तक हो सकता है। कुछ खबरों में 100फीसदी पेनल्टी की बात भी हो रही है, जो भारत-अमेरिका व्यापार को पूरी तरह बर्बाद कर देगी।

कांग्रेस के राजीव शुक्ला- ट्रम्प देशों को धमका रहे हैं। वे भारत से रूस के साथ व्यापार न करने के लिए कह रहे हैं। यह बहुत गलत है। अमेरिका भारत का समर्थन नहीं कर रहा है। हम ट्रम्प के साथ दोस्ती का दावा कर रहे थे। वह कहां है। वे कहते हैं, मोदी मेरे दोस्त हैं, लेकिन 25फीसदी टैरिफ लगा रहे, इसका क्या मतलब है। वह भारत के साथ अन्याय कर रहे हैं।

राज्यसभा सांसद जयराम रमेश- हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प से कोई फायदा नहीं हुआ। हमें इस दोस्ती से क्या मिला। यह हमारे देश, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका है। पीएम को डरना नहीं चाहिए। अमेरिका की ब्लैकमेलिंग हमारे लिए मुसीबत का समय है। हम सोचते थे हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं - पाकिस्तान और चीन, लेकिन अमेरिका तीसरी बड़ी मुसीबत बनकर उभरा है।

मालेगांव केस: 'सनातन धर्म को बदनाम करने वालों को माफी मांगनी चाहिए'- रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली । मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट द्वारा सातों आरोपियों को बरी किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोटबैंक की राजनीति के लिए हिंदू आतंकवाद का झूठ गढ़ा और देश की संस्कृति 'सनातन धर्म' को बदनाम किया। साथ ही पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बिना शर्त माफी की मांग की है। भाजपा नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक जीत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के उदय को रोकने के लिए यह हिंदू आतंक का षड्यंत्र रचा। उन्होंने मांग की कि मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी किए गए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को मुआवजा मिलना चाहिए।

गौरव भाटिया बोले- पूरा धर्म बदनाम किया गया

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अदालत के इस फैसले ने कांग्रेस की साजिश को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस ने निर्दोष लोगों को आतंकवादी बताया और पूरे सनातन धर्म को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या वे हिंदुओं से माफी मांगेंगे?

अमित मालवीय ने बताया कांग्रेस की षड्यंत्रकारी राजनीति

भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने भगवा आतंक का झूठ फैलाया जो अब पूरी तरह से ढह चुका है। उन्होंने कहा कि यह साजिश कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, पी. चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे की अगुवाई में रची गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूरे देश के हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए।

निशिकांत दुबे का बयान- आतंकवादियों को बचाती रही कांग्रेस

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 2005 से 2013 के बीच हुए आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका को छुपाने की कोशिश की और उल्टा देश के भीतर हिंदू आतंक का झूठ फैलाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यही मानसिकता उसे चीन समर्थक राजनीति करने पर भी मजबूर करती है।

एक किमी से ज्यादा दूरी वाले और 50 से ज्यादा विद्यार्थियों वाले स्कूलों का नहीं होगा विलय

लखनऊ ।

यूपी में कम नामांकन वाले सरकारी स्कूलों के विलय को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए आदेश दिया गया है कि अब एक किमी से ज्यादा दूरी वाले स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाएगा।

वहीं, ऐसे स्कूल जहां पर विद्यार्थियों की संख्या 50 से ज्यादा है उनका भी विलय नहीं किया जाएगा। ये आदेश यूपी के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने दिया है। बता दें कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में शिक्षक संघ और अभिभावक प्रदेश सरकार के स्कूलों के विलय के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान कई ऐसी भी शिकायतें आई हैं जिनमें अभिभावकों ने विलय के बाद नये स्कूल के काफी दूर होने की शिकायत की।

इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस मौके पर लोकभवन में मीडिया को संबोधित करते हुए बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि बीते आठ वर्षों में परिषदीय स्कूलों की स्थिति में काफी सुधार आया है। सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास

कर रही है कि हर बच्चे को शिक्षा के अधिकार के तहत अच्छी शिक्षा मिले। इसके लिए स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 2017 के बाद स्कूलों के हालात सुधारने के प्रयास किए गए जिसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश के 96 प्रतिशत स्कूलों में बच्चों के लिए पीने का पानी, शौचालय और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश कोई पहला राज्य नहीं है जहां पर स्कूलों की पेयरिंग (विलय) की जा रही है। इसके पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा जैसे राज्यों में यह प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है। संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल और बच्चों के भविष्य को और बेहतर कैसे बना सकते हैं इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। राजस्थान में 2014 में इस प्रक्रिया के तहत 20 हजार स्कूलों का विलय किया गया। मध्य प्रदेश में 2018 में पहले चरण में 36 हजार विद्यालयों को और लगभग 16 हजार समेकित परिसरों को निर्मित किया गया।

उड़ीसा में 2018-19 में 1800 विद्यालयों को पेयर किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी 2022 व 2024 में चरणबद्ध तरीके से पेयरिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की अंतिम सूची तैयार

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि उसने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की अंतिम सूची तैयार कर ली है। यह चुनाव जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के कारण जरूरी हो गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते है। आयोग ने एक बयान में कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है।

साध्वी प्रज्ञा-कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपी बरी

नई दिल्ली । महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए बम धमाके के मामले में मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया।

इस केस के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी सबूत विश्वसनीय नहीं है। कोर्ट द्वारा इस मामले में जिन प्रमुख आरोपियों को बरी किया है उनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी भी इस मामले में आरोपी थे, जिन्हें अदालत ने निर्दोष पाया।

कोर्ट का अहम फैसला और टिप्पणियां-

स्पेशल जज लाहोटी ने फैसला सुनाते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं

सबूतों का अभाव- अदालत ने जोर देकर कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे उनके अपराध को साबित किया जा सके।

आरडीएक्स पर स्पष्टता नहीं- कोर्ट ने पाया कि यह साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि कर्नल पुरोहित आरडीएक्स लाए थे या बम को असेंबल किया गया था।

मोटरसाइकिल बम की स्थिति- अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बम मोटरसाइकिल के बाहर रखा गया था, न कि अंदर। यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि बम वाली मोटरसाइकिल किसने खड़ी की, खासकर तब जब घटना स्थल रमजान के चलते पहले से सील किया गया था।

अन्य घटनाओं पर अस्पष्टता- घटना के बाद की स्थितियों जैसे पत्थरबाजी, नुकसान पहुंचाना या पुलिस की बंदूक छीनने जैसी घटनाओं पर भी कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला।

मेडिकल प्रमाण पत्र- कुछ मेडिकल प्रमाण पत्र अवैध चिकित्सकों द्वारा जारी किए गए थे, जिन्हें अदालत में साबित नहीं किया जा सका।

एटीएस कार्यालय पर तर्क खारिज- बचाव पक्ष के इस तर्क को कि एटीएस का कालाचौकी कार्यालय एक पुलिस स्टेशन नहीं है, अदालत ने अस्वीकार कर दिया।

धमाका और शुरुआती जांच (29 सितंबर 2008)- मालेगांव के भीकू चौक पर एक दोपहिया वाहन में बम विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 101 लोग घायल हुए थे। मृतकों में फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख लियाकत, शेख मुश्ताक यूसुफ, शेख रफीक मुस्तफा, इरफान जियाउल्लाह खान, सैयद अजहर सैयद निसार और हारून शाह मोहम्मद शाह शामिल थे।

शुरुआत में इस मामले की एफआईआर स्थानीय पुलिस ने दर्ज की थी, लेकिन बाद में जांच एंटी टेररिज्म स्क्वॉड को सौंप दी गई।

एटीएस की चार्जशीट- एटीएस ने अपनी जांच में दावा किया कि अभिनव भारत नामक एक संगठन 2003 से एक संगठित अपराध गिरोह की तरह काम कर रहा था। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय सहित कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया था।

यह फैसला इस लंबे समय से चल रहे कानूनी मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं।